



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष २, अंक १६]

सोमवार, जून २७, २०१६/आषाढ ६, शके १९३८

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २२

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

नगर विकास विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित १६ जून २०१६।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XII OF 2016.

AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL
CORPORATIONS ACT.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १२, सन् २०१६।

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनो सदनों का सत्र नहीं चल रहा है;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, सन १९४९ जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों कि लिए, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन का ५९। करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल एतद्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं अर्थात्:—

(१)

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा
प्रारम्भण ।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ कहलाए ।
(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

अध्याय दो

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन

सन् १९४९ का
५९ की धारा ५
में संशोधन ।

२. महानगर नगर निगम अधिनियम (जिसे इसमें, इस अधिनियम में, “नगर निगम अधिनियम” सन् १९४९ का ५९ । कहा गया है, की धारा ५ की उप-धारा (२), के खण्ड (क) की तालिका में—

(क) प्रविष्टि (तीन) के स्तंभ (२) में “१४५ से अनधिक होगा” शब्दों तथा अंकों के स्थान में “१५१ से अनधिक होगा” शब्द तथा अंक रखे जायेंगे ;

(ख) प्रविष्टि (चार) के स्थान में, निम्न प्रविष्टियाँ, रखी जायेगी, अर्थात् :—

“ (चार) २४ लाख से उपर
तथा ३० लाख तक ।

निर्वाचित पार्षदों की न्यूनतम संख्या
१५१ होगी ।

२४ लाख से उपर प्रत्येकी अतिरिक्त ५०,००० की जनसंख्या के लिए, एक अतिरिक्त पार्षद दिया जायेगा, तथापि, इस प्रकार से निर्वाचित पार्षदों की न्यूनतम संख्या १६१ से अनधिक होगी ।

(पाँच) ३० लाख से उपर ।

निर्वाचित पार्षदों की न्यूनतम संख्या
१६१ होगी ।

३० लाख से उपर प्रत्येकी १ लाख की प्रत्येकी अतिरिक्त जनसंख्या के लिए एक अतिरिक्त पार्षद दिया जायेगा । तथापि, इस प्रकार से न्यूनतम निर्वाचित पार्षदों की संख्या १७५ से अधिक नहीं होगी । ” ।

अध्याय तीन

विविध

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति ।

३. (१) इस अध्यादेश द्वारा, यथा संशोधित नगर निगम अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबंधों से अन असंगत कोई ऐसे निदेश दे सकेगी, जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतित हो ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

वक्तव्य

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) की धारा ५, निर्वाचित के साथ-साथ नामित पार्षदों से मिलकर निगम का गठन करने के लिये उपबंध करती है। उक्त धारा ५ की उप-धारा (२) का खण्ड (क), संबंधित निगमों की जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित होने वाले पार्षदों की संख्या विनिर्दिष्ट करने के लिये समानुपात के लिये उपबंध करती है।

उक्त धारा ५ की उप-धारा (४) यह उपबंध करती है कि, जहाँ सामान्य निर्वाचितों के पश्चात्, शहर का क्षेत्र विस्तारित हुआ है, वहाँ विस्तारित क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध करने के लिये निर्वाचन, यथासंभव शीघ्र लिया जायेगा। उक्त उप-धारा (४) का प्रथम परंतुक यह उपबंध करता है कि, उस उप-धारा के अधीन विस्तारित क्षेत्र के लिये नये रूप से गठित प्रभागों समेत, शहर में के प्रभागों की कुल संख्या, उप-धारा (२) के खण्ड (क) की तालिका में विनिर्दिष्ट निर्वाचक प्रभागों की संख्या से अधिक नहीं होगी। उक्त उप-धारा (४) का द्वितीय परंतुक यह उपबंध करता है कि, उप-धारा (४) के अधीन नये रूप से गठित प्रभागों की जनसंख्या, अन्य प्रभागों की औसत में सीमित रूप से अधिक या निम्न हो सकेगी।

२. उप-धारा (२) के खण्ड (क) की, तालिका में प्राप्त विद्यमान उपबंधों के अनुसार २४ लाख से अधिक जनसंख्या के लिये, निर्वाचित किये जानेवाले पार्षदों की न्यूनतम संख्या १४५ हैं। उक्त तालिका यह भी उपबंध करती है कि, २४ लाख से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त १ लाख जनसंख्या के लिये, निर्वाचित पार्षदों की अधिकतम संख्या २२१ पर निर्धारित की गई है, के अध्यधीन, एक अतिरिक्त पार्षद होगा।

३. सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि कतिपय मामलों में, भले ही, अतिरिक्त क्षेत्रों के समावेशन द्वारा नगर निगम का क्षेत्र विस्तारित किया गया है, निर्वाचित पार्षदों द्वारा निगम के ऐसे विस्तारित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है, जैसा कि उक्त तालिका यह उपबंध करती है कि, जहाँ २४ लाख से अधिक निगम की जनसंख्या है, वहाँ २४ लाख से अधिक प्रत्येक १ लाख जनसंख्या के लिये एक अतिरिक्त पार्षद होगा। इस प्रकार, कतिपय मामलों में, ऐसे निगम के ऐसे विस्तारित क्षेत्र प्रतिनिधित्व के बिना शेष रहते हैं।

४. इस विषमता को हटाने के लिये, २४ लाख से अधिक जनसंख्या होनेवाले निगमों के संबंध में, अतिरिक्त पार्षद के लिये जनसंख्या की विहित प्रमात्रा को कम करना प्रस्तावित है, और तदनुसार, यह भी प्रस्तावित है कि, निर्वाचित पार्षदों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या तथा निगम के निर्वाचित पार्षदों की संख्या में वृद्धि के लिये जनसंख्या का अनुपात का पुनरीक्षण हो। ऐसे उपबंधों से विस्तारित क्षेत्रों की जनसंख्या के बहुमत का निगम में प्रतिनिधित्व किए जाने की सुनिश्चितता होगी। अतः, इसलिये, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, की धारा ५ में यथोचित संशोधन करने का प्रस्तावित किया गया है।

५. क्योंकि, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं कि, जिनके कारण उन्हें, इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) में अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

महाराष्ट्र के राज्यपाल।

मुंबई,

दिनांकित १४ जून २०१६।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

सरकार के सचिव।

(यथार्थ अनुवाद)

डॉ. मंजुषा कुलकर्णी,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।